



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष पर मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने प्रदेश के विकास के लिए पूजा की

डीग/जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष 2025 के प्रथम दिन बुधवार को डीग के श्रीनाथ जी मन्दिर, मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर के मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर में दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर प्रदेश के विकास और आमजन की खुशहाली की कामना की। इस सभ्यता की धर्मशाली भी साथ में थीं। शर्मा डीग जिले के श्रीनाथ जी मन्दिर में मंगला आरती में शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने मुकुट मुखारविंद मन्दिर में श्री गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक किया तथा विधिवत पूजा-अर्चना की।

इस अवसर पर, भरतपुर रेंज आई जी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर डीग उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर

■ उन्होंने पूंछरी का लौठा में श्रीनाथ जी मन्दिर व मुकुट मुखारविंद मन्दिर तथा जयपुर में मोतीदुंगरी गणेश जी मन्दिर में पूजा-अर्चना की।

डीग संतोष कुमार मीणा सहित, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके बाद, मुख्यमंत्री जयपुर पहुंचे और मोतीदुंगरी गणेश मन्दिर गए, जहाँ उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की। इस अवसर पर गुजरात मंत्री जवाहर सिंह बेदम सहित, जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

अब फ्लाइट में मिलेगा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होगा। इसी के साथ ही तमाम भारतीय एयरलाइंस में एयर इंडिया पहली एयरलाइंस बन गई है, जिसमें अपनी फ्लाइट में वाई-फाई सर्विस शुरू कर दी है। एयर इंडिया ने बताया कि शुरूआत में यह सर्विस उसके 300 से अधिक एयरक्राफ्ट के बेड़े में से कुछ ही एयरक्राफ्ट में शुरू की गई है। इनमें सभी छह ए-350, सात बोइंग-787-9 और 10 ए-321 नियों में से चुनिंदा प्लेन में। एयर इंडिया के बेड़े में अभी 10 ए-321 नियों एयरक्राफ्ट है।

जलगांव में दो गुटों में हिंसा

जलगांव, 01 जनवरी। महाराष्ट्र के जलगांव के पारधी में 31 दिसंबर की रात मंत्री गुलाब राव पाटिल के समर्थकों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इसके बाद भीड़ ने 6 गाड़ियों और 15 दुकानों में आग लगा दी। देर रात फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इसके बाद जलगांव में 2 जनवरी को सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पलाढी गांव में 31 दिसंबर की रात पथराव और आगजनी की घटना हुई है। कर्नाट तौर पर मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को जो लारे वाहन के ड्राइवर द्वारा हार्न बजाने से विवाद पैदा हुआ। इसके बाद पलाढी गांव के कुछ युवक और शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता चिल्लाने लगे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पलाढी गांव में पथराव और आगजनी की।

पुलिस ने इस घटना के बारे में कहा है कि बहस मौके पर ही खत्म हो गई थी। हालांकि, लेकिन बाद में इलाके के कुछ लोग गांव के चौराहे पर गए और विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद एक और समूह वहां पहुंचा, जिसके बाद झड़पें शुरू हो गईं। पुलिस ने कहा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है।

केन्द्र ने फसल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी कम होगी। सरकार ने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए 4 करोड़ और किसानों को इसमें शामिल करने का फैसला किया है। इससे अधिक किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने डीएपी बैंग 1,35,00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे किसानों की 50 किलो का डीएपी बैंग 1,35,00 रुपये में मिलता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार ने यह फैसला किसानों को राहत देने के लिए किया है। सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपये का आउटपुट किया है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि का बोझ किसानों पर न पड़े, इसलिए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है।

इस वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर रहेगा

■ रक्षा मंत्रालय के सभी सचिवों की बैठक में राजनाथ सिंह ने घोषणा की।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों सहित, केन्द्रित हस्तक्षेप के लिए व्यापक क्षेत्रों की पहचान की है। इसके अलावा, भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाएं भी विकसित की जाएंगी। एक अन्य क्षेत्र, जिसकी पहचान की गई है, वह है अधिग्रहण प्रक्रियाएं, जिन्हें तेज और मजबूत क्षमता विकास की सुविधा के लिए सरल और समय-संचालित बनाने की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और ज्ञान साझा करने को सुविधाजनक बनाने, व्यापार करने में आसानी में सुधार करके सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

भारत-पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक-दूसरे को सौंपी

प्रधान भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु स्थानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत किया गया है, जिस पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और 27 जनवरी 1991 को यह लागू हुआ था। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान हरेली जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह दोनों देशों के बीच ऐसी सूचियों का लगातार 34वां आदान-प्रदान है, पहला आदान-प्रदान एक जनवरी 1992 को हुआ था।

‘भाजपा ने मेरे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के बाद देखा गया था। “इन नये वोटों को कौन लाया था? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। ऐसा ही खेल वे इस बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि जो लोग अब दिल्ली में नहीं रहते, जो लोग मर गये हैं, उनके नाम सूची में क्यों हों?” केजरीवाल ने अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि वे भाजपा के हुकूम पर अनियमितताएं नहीं करें। “मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों पर गलत काम करने के लिए दबाव डाला जायेगा, लेकिन याद रखिये, कागजात पर आप हस्ताक्षर करेंगे, और वे हस्ताक्षर बने रहेंगे।

आज या कल, सरकार बदलेगी, लेकिन फाइलें और हस्ताक्षर बने रहेंगे। अनियमितताएं के अनुसार काम करना, करना आप संघटन में पड़ जायेंगे। आदेश देने वाले लोग तो बच कर निकल जायेंगे।”

आप नेता ने भागवत को सितम्बर में भी एक पर लखा तथा भाजपा और उसके नेतृत्व संबंधित पांच सवाल उसने पूछे थे। पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काजें, एन डी ए सरकार द्वारा अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को निशाना बनाने के लिए केन्द्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाये गये थे।

जीवित नहीं निकल पाई 3 साल की चेतना बोरवैल से

समानांतर सुरंग खोदकर 170 फीट नीचे से 10 दिन बाद शव निकाल पाई एन.डी.आर.एफ. टीम

कोटपतली 01 जनवरी (निस)। कोटपतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी (3) को 170 फीट गहरे गड्ढे से दस दिन बाद बाहर निकाला, हालांकि बच्ची को जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची

■ एन.डी.आर.एफ. के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी थी। अंगुली से उसकी बॉडी के आस-पास से मिट्टी हटाई, फिर उसे बाहर निकाल सके।

■ चेतना जब गिरी थी तब 25 फीट पर अटकी हुई थी। परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर अपने स्तर पर ही रस्सी डालकर निकालने का प्रयास किया। आशंका है हाथ ऊपर करने से चेतना फिसल कर 80 फीट गहरी तक चली गई थी।

को अचेत अवस्था में निकाला गया है, जब उसे निकाला गया, तब उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। बुधवार शाम 6 बजकर 25 मिनट पर तीन साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद

चेतना को एंबुलेंस से कोटपतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जांच के बाद डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को किरतपुरा के बड़ियाली की ढागी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिश फेल हुई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन को

प्लानिंग पर भी सवाल उठते रहे। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने बताया कि चेतना की बॉडी मिट्टी के बीच फंसी हुई थी। बोरवेल में घुसने के बाद अंगुली से उसकी बॉडी के आसपास से मिट्टी

मुख्यमंत्री करेंगे हजार करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. की मासिक समीक्षा

सौ से हजार करोड़ के एम.ओ.यू. की समीक्षा मुख्य सचिव तथा सौ से नीचे की विभागीय सचिव करेंगे

जयपुर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन विजन एवं रोडमैप के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में कार्यकाल के पहले ही वर्ष में राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद हस्ताक्षरित हुए एमओयू के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री ने त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल की है।

एमओयू की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था के अनुसार, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले

■ राजिंज राजस्थान में प्रदेश में निवेश के लिये हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये राज्य सरकार ने तीन स्तरीय समीक्षा व्यवस्था बनाई है।

■ राजिंज राजस्थान के तहत 261 एम.ओ.यू. 1,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि के हैं। सौ से एक हजार करोड़ रूपए के एम.ओ.यू. की संख्या 1,678 है। सौ करोड़ तक के कुल 9,726 एम.ओ.यू. हुए हैं।

एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी। वहीं, 100 करोड़ से लेकर 1 हजार करोड़ रुपये तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से की जाएगी।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी।

राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत कुल 35

लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू किए गए थे, जिनमें से लगभग 32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओयू एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वाले हैं। इसी तरह, 100 करोड़ से अधिक एवं 1 हजार करोड़ रुपये से कम की राशि वाले एमओयू की संख्या 1 हजार 678 तथा इनकी कुल राशि साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

साथ ही, 100 करोड़ रुपये तक के एमओयू की संख्या 9,726 तथा इनकी कुल राशि लगभग 90 हजार करोड़ रूपए है।

उल्लेखनीय है कि 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित राजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षरित हुए एमओयू की प्रगति-रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखने की घोषणा करते हुए, अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी थी। इस दिशा में त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था की पहल कारगर साबित होगी।

यूक्रेन ने यूरोप को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) व्यवस्था से अक्सर अड़चन आ जाती है। हाल ही में यूरोप वैकल्पिक रूट के लिए विचार कर रहा है। ऐसा ही एक वैकल्पिक रूट तुर्की से होकर गुजरता है जो यूक्रेन रूट की तुलना में दक्षिणी की ओर ज्यादा है। वैकल्पिक मार्ग के साथ एक समस्या यह भी है कि वे ज्यादा लम्बे हैं।

तहव्वुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) था। हालांकि, कोर्ट ने भारत में किए गए हमलों के आरोपों को खारिज कर दिया लेकिन माना कि वह मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल रहा था, और उसे भारत प्रत्यर्पण किया जाना चाहिए।

केजरीवाल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है। त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आर.एस.एस. और उससे सम्बद्ध संगठनों से सेवा-भावना सीखनी चाहिए तथा अपने राजनैतिक उद्देश्यों को पीछे छोड़ दीजिये।”

कश्मीर में जैश के चार सहयोगी पकड़े

श्रीनगर, 01 जनवरी। जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा उप-जिले में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चार आतंकवादी सहयोगियों की पहचान कर ली है।

ये हैं ज़ाल पाईन के मुदासिर अहमद नाइक, कुचमुल्ला के उमर नजीर शेख, ज़ाल पाईन के इनायत फ़िरदौस राथर और कौसरबल ज़ाल निवासी नजीर अहमद लोन।

एक पुलिस बयान में कहा गया, गिरफ्तार किए गए सभी आतंकवादी सहयोगी ज़ाल और अवंतीपोरा इलाकों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय आतंकवादियों को रसद सहायता और परिचयों और गोला-बारूद के परिवहन में शामिल थे।

इसमें कहा गया है कि उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्रियों का भारमद की गई। ज़ाल बयान में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

आठ पाकिस्तानियों को बीस साल की सजा सुनाई

इन्हें गुजरात तट पर 232 किलो हेरोइन के साथ 2015 में पकड़ा गया था

मुंबई, 01 जनवरी। महाराष्ट्र में मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को आठ पाकिस्तानी नागरिकों को 2015 में गुजरात तट पर 232 किलोग्राम हेरोइन ले जाने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश एस ई बांगर ने आठ आरोपियों को स्वयं कौशल और मन प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी पाया। दोषियों की पहचान अलीबक्शा खखेली सिंधी, मकसूद अख्तर यूसुफ मसिम, मोहम्मद बख्शा नाथ, मोहम्मद अहमद मोहम्मद इनायत, मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला गवानी, मोहम्मद यूनुस हाजी मोहम्मद सुमार सिंधी, मोहम्मद गुलहसन मौलाबख्शा बलूच सिंधी और गुलहसन मोहम्मद सिद्दीक सिंधी के रूप में हुई है। सभी दोषी पाकिस्तानी नागरिक हैं।

■ मछली पकड़ने वाली नाव के साथ पकड़े गये पाकिस्तानी नागरिक 10 साल जेल में बिता चुके हैं। उन्हें 10 साल और सजा भुगतनी होगी।

इन सभी को 2015 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय ये थे लोग जेल में बंद हैं, इसलिए उस अवधि को ध्यान में रखा जाएगा और अब उन्हें जेल में और दस साल बिताते होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में आरोपियों ने मछुआरे होने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी नावों में हेरोइन के पैकेट क्यों थे। वहीं, इन लोगों के पास तीन सैटेलाइट फोन थे, जिनका इस्तेमाल

भारत या पाकिस्तान के नागरिकों को करने की अनुमति नहीं है और नाव पर जीपीएस डिवाइस चार्ज और पाए गए थे, जिससे पता चलता है कि वे भारत जा रहे थे। अदालत ने इस आधार पर मामलों में बरी करने की बचाव पक्ष की याचिका को भी खारिज कर दिया कि मुंबई पुलिस के पास इस मामले को संभालने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जन्मी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि जिस क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई, वह समुद्री अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में है, जो अंतरराष्ट्रीय अधिनियम और नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

बजट 2025-26 में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कम करने के लिए फेसलेस एसेसमेंट सिस्टम लाना शामिल है, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। इन परिवर्तनों से व्यवसायों में भरोसा बढ़ेगा।

भारत में एफ.डी.आई. का प्रवाह हालिया वर्षों में लगातार बढ़ा है और आगामी बजट में ऐसे कदम उठाए जाएंगे कि प्रवाह की ये गति कायम रहे। इससे मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। निर्माण इकाइयों लगाई जाएंगी और यातायात का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा। इसके अलावा, सरकार अक्षय ऊर्जा, ई-वाहन व अन्य क्षेत्रों में प्रोत्साहन दे सकती है। भारत के तेजी से बढ़ते खुदरा बाजार और ई-कॉमर्स सेक्टर में एफ.डी.आई. के निधियों में छूट दी जा सकती है, ताकि अंतरराष्ट्रीय कम्पनियों इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकें।

टैक्सोनॉमी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के एफ.डी.आई. के प्रमुख

क्षेत्र बने रहने की संभावना है। सरकार अतिरिक्त कर लाया था स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन का प्रस्ताव दे सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन और क्लाउड कम्प्यूटिंग में। इन कदमों से भारत को तकनीकी नवचरण में ग्लोबल लीडर बनने में मदद मिलेगी।

रक्षा क्षेत्र, एयरोस्पेस और ई-कॉमर्स में एफ.डी.आई. की मंजूरी की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा, इंटीलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन को मजबूत बनाने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन जाएगा, खासकर टैक्सोनॉमी क्षेत्र में। कायदे-कानूनों का सरलीकरण करने और डिजिटल शासन से सरकार को बिजनेस वातावरण और बेहतर बनने की उम्मीद है और इससे एक पारदर्शी और प्रभावी इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसमें नौकरशाही बाधाएं कम होंगी।